Submitted to : Chief Minister, U.P.
(3A/6805 dt. 14 May 07)

Urgent issues/proposals related to industrial development in the State submitted to Chief Minister.

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन (आई०आई०ए०) जो प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक मात्र संगठन है, आपको स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने, प्रदेश को लम्बे समय के बाद एक स्थिर सरकार देने और देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया का पद सम्भालने पर हार्दिक बधाई देता है।

प्रदेश में लगभग २० लाख सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग स्थित है जिनमें लगभग ७५ से ८० लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त है और ५ करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजी रोटी का साधन उपलब्ध करा रहा है। मुख्यमंत्री का पद सम्भालने के बाद आपके सम्बोधन हमने ध्यान पूर्वक सुने है। आपकी घोषणाओं को कार्यरूप देने में लघु एवं मध्यम उद्योग विशेष भूमिका निभा सकते है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण घोषणा रोजगार सृजन से सम्बन्धित है क्योंकि कृषि के उपरान्त यही उद्योग सबसे अधिक रोजगार प्रदान कर सकते हे।

आज विभिन्न कारणो से प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योग बहुत कठिन दौर का सामना कर रहे है जिसके चलते ७० प्रतिशत से अधिक उद्योग या तो बीमार चल रहे है या बन्द हो चुके है। हमारा पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में न केवल इस उद्योग को जीवनदान मिलेगा परन्तु यह खूब फलेगा फूलेगा और प्रदेश के नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को भी सुदृढ़ करेगा।

आई०आई०ए० आपकी कार्यशैली से भली-भॉति परिचित है अतः हमें ज्ञात है कि आप यह जानना चाहेगी कि इन उद्योगों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार की और से वर्तमान में एवं दीर्घकाल में क्या किया जाना चाहिए। इसलिए निम्नलिखित प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत है जिन्हे वर्तमान अथवा अविलम्ब लागू किये जाने की आवश्यकता है :-

- व्यापार कर प्रणाली एवं प्रक्रिया में व्यापक सुधार की आवश्यकता है जिससे सरकार के राजस्व में वृद्धि हो और उद्योग धन्धे भी प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश को छोड़ पूरे देश में वैट प्रणाली लागू हो गई है और अनेक राज्यों के राजस्व में भी इसे लागू करने से खासी वृद्धी हुई है। तमिलनाडू इसका लेटेस्ट उदाहरण है जहॉ वैट लगने से सरकार के कर राजस्व में ५० प्रतिशत वृद्धि हुई है। अतः प्रदेश में वैट अविलम्ब लागू करने की आवश्यकता है।
- उद्योगो से सम्बन्धित समस्त सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने एवं उसके अनुश्रवण को कारगर बनाने की अविलम्ब आवश्यकता है। यह सूचना प्रोद्योगिकी के उपयोग से सम्भव है। इस हेतु आप द्वारा योग्य एवं जानकार औद्योगिक विकास आयुक्त की पहले ही दिन नियुक्ति कर दी गई है जिसके लिए आई०आई०ए० आपका धन्यवाद व्यक्त करता है। इनकी प्रेरणा एवं प्रयासो से ही आई०आई०ए० द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए एकल बेव आधारित एक मेज व्यवस्था ८ अगस्त २००६ में तैयार की थी परन्तु इस व्यवस्था का विधीवत् उद्घाटन आज तक नही हो पाया है। आशा है आपके कर कमलों द्वारा इस व्यवस्था का उद्घाटन जल्दी ही होकर सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शित लाने का शुभारम्भ हो सकेगा। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि बर्ड

बैंक इन्स्टीटयूशन द्वारा इस नई व्यवस्था का अध्ययन किया गया है और उन्होने इसे बहुत उपयोगी पाया है।

- उद्योग बन्धु प्रदेश में एक बहुत ही उपयोगी संस्थान है जिसके माध्यम से विभिन्न स्तरों पर उद्योगों की समस्याओं का समाधान किया जाता रहा है। इस संस्थान की अहमियत विगत कुछ वर्षो से घटती जा रही है क्योंकि विगत में राज्य स्तर पर इसकी बैठकों में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा समय नही दिया गया है। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की बैठकों की अध्यक्षता तीन महीने में कम से कम एक बार अवश्य करें। ऐसा करने से पूरे प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में सुधार होगा।
- प्रत्येक वर्ष प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों का एक महा सम्मेलन आयोजित किया जाना अतिआवश्यक है। आई०आई०ए० इसका आयोजन करता भी रहा है जब–जब तत्कालीन मुख्यमंत्रीयों ने इसके उद्घाटन हेतु समय दिया है। इस उद्यमी महासम्मेलन के माध्यम से लघु उद्योगो के उद्यमियों एवं सरकार के मध्य सीधा संवाद स्थापित होता है जिससे औद्योगिक वातावरण में सुधार अवश्य होता है। हमारा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के लघु एवं मध्यम उद्योगो के महासम्मेलन के उद्घाटन हेतु आगामी तीन,चार महीनों में सुविधानुसार तिथि निर्धारित करने की कृपा करें।
- प्रदेश में उद्योग निदेशक का महत्वपूर्ण पद विगत ६ महीनों से रिक्त है। इस पद पर किसी सक्षम एवं योग्य अधिकारी की तैनाती अविलम्ब करने की आवश्यकता है।
- प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम करना भी एक प्राथमिकता है जिसके लिए घोषणा एवं कारगार कदम आपने अपने कार्यकाल के एक दिन के अन्दर ही उठा लिये है। आई०आई०ए० आपकी इस पहल के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता है। और आशा करता है कि प्रदेश के उद्यमी निर्भय होकर अपना पूरा ध्यान उद्योग धन्धों की प्रगति में लगा सकेंगें।

उपरोक्त सभी प्रस्तावो में सरकार को कोई भी अतिरिक्त धन खर्च करने की आवश्यकता नही है बल्कि इससे सरकार के राजस्व में वृद्धि ही होगी।